23-05-2023

राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022

समाचार पत्रों में क्यों?

जलशक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विभाग और गंगा कायाकल्प ने नगर निगम चंडीगढ़ को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में प्रथम स्थान दिया है।

त्वरित मुद्दा?

- भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने साल 2022 में चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की घोषणा की है। जिसमें चंडीगढ़ को पहला स्थान मिला है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय श्रेणी में नगर निगम चंडीगढ़ ने पहला स्थान प्राप्त किया है।
- यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रदान किया गया है।
- इसका उद्देश्य जनता को पानी के महत्त्व के बारे में जागरूक करना और उन्हें सर्वोत्तम जल उपयोग प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रेरित करना है।
- चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत राज्यों, संगठनों, व्यक्तियों आदि को 11 अलग-अलग श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।
- राष्ट्रीय जल पुरस्कार 'जल समृद्ध भारत' की परिकल्पना को पूरा करने के काम में देश भर में राज्यों, ज़िलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि द्वारा किये गए अनुकरणीय कार्यों के लिये दिये जाते हैं।

एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कांफ्रेंस 2023

समाचार पत्रों में क्यों?

केंद्रीय स्वास्थ्य, रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने 19 मई, 2023 को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता की।

त्वरित मुद्दा?

- भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (सीपीएमए) ने इस 41वें संस्करण की मेजबानी की।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य - एशिया-प्रशांत और विश्व भर में विकास, व्यापार, निवेश और स्थिरता से संबंधित उद्योग को बढ़ावा देना है।
- इस आयोजन का विषय "एक सतत भविष्य में प्रवेश" था।
- सम्मेलन में सात सदस्य देशों के 1200 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूरोप, चीन, अमेरिका, मध्य पूर्व और अन्य एशियाई देशों और वैश्विक भागीदारों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- भारत रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विश्व में एक विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए प्रतिबद्ध है।
- एशिया पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री कांफ्रेंस :- यह सम्मेलन सात सदस्य देशों-जापान, कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान और भारत द्वारा रोटेशन के आधार पर आयोजित किया जाता है।

अन्य प्रमुख तथ्य?

सीपीएमए के बारे में

- यह भारतीय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला देश का शीर्ष मंच है।
- इसकी स्थापना 1993 में हुई थी।
- यह अपने सदस्यों को सामूहिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने, अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और उद्योग के मुद्दों पर सुझाव देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
- यह बड़े पैमाने पर उद्योग, सरकार और समाज के बीच एक कड़ी प्रदान करता है।

- यह एशिया में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है जो उद्योग के पेशेवरों, विशेषज्ञों और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के हितधारकों को एक साथ लाता है।
- सम्मेलन का उद्देश्य पूरे एशियाई क्षेत्र में ज्ञान के आदान-प्रदान, सहयोग को बढ़ावा देना और पेट्रोकेमिकल उद्योग में चुनौतियों और अवसरों का समाधान करना है।

एफआईपीआईसी शिखर सम्मेलन, 2023

समाचार पत्रों में क्यों?

22 मई 2023 को फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (एफआईपीआईसी) के तीसरे शिखर सम्मेलन के लिए पोर्ट मोरेस्बी की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रशांत द्वीप समूह के देशों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) पाठ्यक्रमों के पूर्व छात्रों से बातचीत की।

त्वरित मुद्दा?

- इस वर्ष के FIPIC शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता सभी 14 देशों के नेताओं की पूर्ण भागीदारी थी। अन्य देशों के देशों के सामने आने की वजह से यह एक दुर्लभ घटना थी। इन देशों के अभिसरण ने भारत और प्रशांत क्षेत्र के बीच संबंध को मजबूत करने के महत्व और क्षमताओं को रेखांकन किया।

Prime Minister's closing statement at the FIPIC III Summit

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि?

- इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC समिट) का तीसरा फोरम, जो आज पोर्ट मोरेस्बी में आयोजित किया गया था, पापुआ न्यू गिनी के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- भारत के प्रधान मंत्री ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधान मंत्री के साथ शिखर सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की।
- इस सम्मेलन में वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल और जलवायु परिवर्तन सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया।
- फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन (FIPIC) भारत और 14 प्रशांत द्वीप राष्ट्रों के बीच सहयोग के लिए एक बहुराष्ट्रीय समूह है।
- इसमें 14 द्वीपों के नाम शामिल हैं- कुक आइलैंड्स, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नीयू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालु और वानुअतु।
- उपरोक्त देशों के सभी राष्ट्राध्यक्ष / सरकार के प्रमुख नवंबर 2014 में पहली बार सुवा, फिजी में मिले थे जहां वार्षिक शिखर सम्मेलन की परिकल्पना की गई थी।
- एफआईपीआईसी (FIPIC) पहल प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी का विस्तार करने के लिए एक गंभीर प्रयास का प्रतीक है।

न्यूज फटाफट

ऑपरेशन ध्वस्त

- संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) ने 'ऑपरेशन ध्वस्त' लॉन्च किया है।
- इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करने वाले आतंकवादी समूहों, गैंगस्टर्स और ड्रग तस्करों से जुड़े गठजोड़ को समाप्त करना है।
- इसके तहत एन.आई.ए. ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय में छापेमारी करके नियोजित ऑपरेशन शुरू किया।
- एन.आई.ए. का गठन राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया है। यह भारत में केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

वर्ल्डकॉइन (WORLDCOIN)

- वर्ल्डकॉइन ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन द्वारा प्रस्तावित एक क्रिप्टो परियोजना है।
- इसका उद्देश्य सभी के लिये एक वैश्विक पहचान और वित्तीय नेटवर्क का निर्माण करना है।
- यह ओर्ब नामक एक डिवाइस का उपयोग करता है जो लोगों की अद्वितीय मानवीय पहचान स्थापित करने के लिये आंखों की पुतलियों को स्कैन करता है।
- वर्ल्डकॉइन और अन्य डिजिटल संपत्तियों का उपयोग करके भुगतान, खरीद और हस्तांतरण को सक्षम बनाने के लिये इसमें एक वर्ल्ड ऐप भी है।

सतत् भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र

- सतत् भूमि प्रबंधन हेतु उत्कृष्टता केंद्र (CoE-SLM) का औपचारिक उद्घाटन 20 मई, 2023 को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE), देहरादून में किया गया।
- इस पहल की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेज़र्टिफिकेशन (UNCCD) के 14वें सम्मेलन (COP-14) के दौरान की गई थी।
- CoE-SLM का उद्देश्य स्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से भूमि क्षरण के मुद्दों से निपटना, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना और भूमि निम्नीकरण तटस्थता (LDN) में योगदान करना है।
- तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण एवं ज्ञान साझा कर CoE-SLM का इरादा खराब भूमि को बहाल करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और लक्ष्यों जैसे कि SDG, जैविक विविधता पर सम्मेलन तथा UNFCCC के साथ संरेखित करना, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और जैवविविधता हानि पर भूमि क्षरण के प्रभावों का समाधान करना है।
- CoE-SLM की स्थापना पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

हीटवेव

- वर्ल्ड वेदर एट्रिब्यूशन (WWA) के एक अध्ययन में पाया गया कि अप्रैल में होने वाली तीव्र और आर्द्र गर्मी की लहरें जो पूर्वी और उत्तर भारत, बांग्लादेश, लाओस एवं थाईलैंड जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत अधिक होने की संभावना थी।

- इस तरह की हीटवेव होने की संभावना कम से कम 30 गुना बढ़ जाती है।
- ह्यूमिड हीटवेव का विश्लेषण हीट इंडेक्स का उपयोग करके किया जाता है जो बढ़े हुए तापमान और सापेक्ष आर्द्रता के स्तर का एक संयोजन है।
- इसके द्वारा मानव शरीर पर हीटवेव के प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करता है।
- भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मानदंड के अनुसार, जब तक किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिये कम-से-कम 40°C और पहाड़ी क्षेत्रों के लिये कम-से-कम 30°C तक नहीं पहुँच जाता तब तक "लू" पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि किसी स्टेशन का सामान्य अधिकतम तापमान 40°C से कम या उसके बराबर है तो सामान्य तापमान से 5°C से 6°C की वृद्धि को हीटवेव स्थिति माना जाता है।
- इसके अतिरिक्त सामान्य तापमान से 7 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक की वृद्धि को गंभीर "लू" की स्थिति माना जाता है।
- WWA, जलवायु वैज्ञानिकों का एक वैश्विक संघ है जो मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन द्वारा निभाई गई भूमिका का अध्ययन करता है,जैसे गर्मी की लहरों, सूखा, ठंड, अत्यधिक वर्षा, बाढ़ और तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता आदि।

CCI और ECA के बीच समझौता ज्ञापन

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) और मिस्र के प्रतिस्पर्द्धा प्राधिकरण (ECA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर करने को मंज़ूरी दे दी है।
- समझौता ज्ञापन, सूचना के आदान-प्रदान और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ विभिन्न क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से प्रतिस्पर्द्धा कानून एवं नीति में सहयोग को बढ़ावा देने व इसे मज़बूत करने की परिकल्पना पर आधारित है।
- समझौता ज्ञापन का उद्देश्य CCI और ECA के बीच संबंधों को विकसित एवं मज़बूत कर अनुभव साझा करना, तकनीकी सहयोग के माध्यम से अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में प्रतिस्पर्द्धा कानून के प्रवर्तन में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना और अनुकरण करना है।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 की धारा 18 CCI को अधिनियम के तहत अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने या अपने कार्यों को करने के उद्देश्य से किसी भी अन्य देश की किसी भी एजेंसी के साथ किसी भी ज्ञापन या व्यवस्था में प्रवेश करने की अनुमति देती है।
- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002, भारतीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को नियंत्रित करता है और गैर-प्रतिस्पर्द्धी प्रथाओं जैसे कार्टेल, प्रमुख बाज़ार स्थिति का दुरुपयोग और विलय एवं अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है जो प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा अधिनियम में संशोधन किया गया है।

जाति-आधारित सर्वेक्षण

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक हटाने के आदेश को वापस कर दिया है। बिहार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्तर पर आँकड़े एकत्र करने के लिये सर्वेक्षण शुरू किया था।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि यह एक सर्वेक्षण जनगणना थी या स्वैच्छिक अभ्यास।
- जाति-आधारित सर्वेक्षण एक क्षेत्र या देश में विभिन्न जातियों की जनसंख्या पर जानकारी एकत्र करने की एक प्रक्रिया है।
- जाति, जन्म, व्यवसाय और धर्म के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण की एक प्रणाली है।
- पिछड़े वर्गों की पहचान करने के साथ आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएँ प्रदान करने के लिये सामान्य रूप से जाति-आधारित सर्वेक्षण किये जाते हैं।
- हालाँकि जाति-आधारित सर्वेक्षण भी विवादास्पद हैं क्योंकि वे सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं।
- प्रतिनिधित्व और व्यक्तिगत गोपनीयता अनुच्छेद 340 सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच करने और सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का आदेश देता है।

KAUTILYA ACADEMY INDORE